



2026:AHC:65769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 12558 वर्ष 2026

अर्पित कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: डीके ओझा, प्रदीप कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना; राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें एन.आई. एक्ट के अतिरिक्त न्यायालय, कमरा संख्या-2, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 26.05.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत आपराधिक मामला संख्या-633 वर्ष 2022 में दायर एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए के तहत अंतरिम आवेदन की अनुमति दी गई है और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-338 वर्ष 2023 (अर्पित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कमरा संख्या-6, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 को पारित किया गया है।
3. शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि विवादित संपत्ति, प्लॉट सं -जी-56, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी इलाहाबाद से संबंधित है, जिसे सरकार ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा वित्तीय निगम से नीलामी के माध्यम से खरीदा गया था और बिक्री विलेख वर्ष 1996 में निष्पादित किया गया था। विवादित भूखंड प्रतिपक्षी संख्या-2 की फर्म के नाम पर था। 1,28,00,000/- रुपये की बिक्री के विचार के लिए एक विलेख तैयार किया गया था और उस भूखंड के हस्तांतरण के लिए 50,000/- रुपये अग्रिम के रूप में हस्तांतरित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए गए थे। यह सहमति हुई कि आवेदक 40 लाख रुपये हस्तांतरित करेगा और शेष 87,50,000/- रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे जब सिडबी से ऋण आवेदक को वितरित किया जाएगा। जब शिकायतकर्ता ने 87,50,000/- रुपये का चेक प्रस्तुत किया, तो अपर्याप्त निधि के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान शिकायत दर्ज की गई है। मामले के लंबित रहने के दौरान, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने धारा 143A एन.आई. अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 26.05.2023 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। आवेदक ने आपति दर्ज की और प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 को चेक दिया है और प्रतिपक्षी संख्या-2 ने बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया है और नकदीकरण के लिए चेक जमा किया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने क्रि. पुनरीक्षण संख्या-338 वर्ष 2023 दाखिल करके दिनांक 26.05.2023 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे भी दिनांक 20.10.2023 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक की आपति पर विचार करने के बाद दिनांक 26.05.2023 का आदेश पारित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों आदेश अवैध हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं। आवेदक के अधिवक्ता ने **राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2024 उच्चतम (एस.सी.) 229** में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने अंतरिम मुआवजे के लिए धारा 143 ए एन.आई. अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के आवेदन पर निर्णय लेते समय आवेदक द्वारा उठाई गई आपति पर विचार किया है कि उसने चेक को सुरक्षा के रूप में जारी किया है, लेकिन इसका उपयोग धोखाधड़ी से किया गया है और इसे भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने आपति पर विचार किया है और पाया है कि आवेदक द्वारा उठाई गई आपति तथ्य का विवादित प्रश्न है और इसका पता मुकदमे के चरण में लगाया जा सकता है। आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है और एन.आई.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धारा 143 ए के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए(4) में प्रावधान है कि:

"यदि चेक के आहर्ता को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे की राशि को चुकाने का निर्देश देगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रचलित है, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए जा रहे पर्याप्त कारण पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, तीस दिनों से अधिक नहीं है।

6. धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित है और सबूत पेश किए जाने बाकी हैं और निर्णय आना बाकी है। विचारण न्यायालय को पक्षगण द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करनी है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबमिशन की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है। अधिनियम में प्रावधान है कि आवेदक के बरी होने की स्थिति में शिकायतकर्ता से राशि वसूल की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने लगभग ढाई साल बाद आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है और आज तक, आवेदक ने प्रतिपक्षी संख्या-2 को कोई राशि नहीं दी है। अदालत ने राकेश रंजन श्रीवास्तव (उपरोक्त) में निर्धारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मापदंडों का पालन करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया है। इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. प्रस्तुत आवेदन, तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

मीनू सिंह

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)